

संपादकीय

रोजगार की भयावह तस्वीर

वर्तमान सरकार के कुछ कदम बेरोजगारी को बढ़ाने वाले रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह समस्या व्यवस्थागत है। जब तक उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसका कोई समाधान नहीं निकल सकता। भारत में बेरोजगारी की समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इसके बावजूद यह मुख्य राजनीतिक विमर्श का हिस्सा नहीं है। विपक्षी नेता जब-तक इस समस्या का जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन समस्या क्यों है और उसका समाधान क्या है, इन सवालों पर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। उनका सिर्फ यह कहना होता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने बेरोजगारी बढ़ा दी है। बेशक, वर्तमान सरकार के कुछ कदम बेरोजगारी को बढ़ाने वाले रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह समस्या व्यवस्थागत है। जब तक उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसका कोई समाधान नहीं निकल सकता। फिलहाल, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की ताजा रिपोर्ट चर्चा में है, जिसमें बताया गया है कि भारत में 15 प्रतिशत से ज्यादा ग्रैजुएट बेरोजगार हैं। 25 साल से कम उम्र के ग्रैजुएट्स के बीच तो बेरोजगारी दर 42 प्रतिशत तक है। 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया-2023' रिपोर्ट में भारत में रोजगार की चिंताजनक तस्वीर पेश की है। बताया गया है कि 2019 के बाद से भारत में नियमित वेतन की नौकरियों के सृजन की रफतार कम हुई है। इसका एक बड़ा कारण कोविड-19 महामारी रही। महामारी के बाद रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ। ग्रैजुएट लोगों को नौकरियां मिलने लगीं। लेकिन सवाल बना हुआ है कि उन्हें किस तरह की नौकरियां मिल रही हैं और क्या ये उनके कौशल और आकांक्षाओं से मेल खाती हैं? जाहिर है, ऐसी स्थिति नहीं है। हाल ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर कुली कर्मियों से संबाद किया। उस दौरान सामने आया कि कुछ ग्रैजुएट कुली का काम कर रहे हैं। महिलाओं में तो रोजगार की दर 2004 के बाद से या तो रुकी हुई रही या गिरी है। 2019 के बाद से महिलाओं के बीच घरेलू अर्थिक दबाव के कारण स्वरोजगार का ट्रैंड जरूर बढ़ा है। लेकिन अपने देश की यह हकीकत कायम है कि स्वरोजगार अक्सर मजबूरी में किया जाता है और ज्यादातर मामलों में इसका अर्थ अर्ध-रोजगार होता है। खुद रिपोर्ट में बताया गया है कि नियमित वेतन वाली नौकरी की जगह महिलाओं के बीच स्वरोजगार बढ़ा और इस वजह से उनकी आमदानी घट गई।

विचार

पितृपक्ष में क्या करेंगी पार्टियां?

श्राद्ध का समय शुरू हो गया है। अगले 15 दिन तक हिंदू मान्यता के हिसाब से कोई शुभ काम नहीं होगा और न कोई नया काम शुरू किया जाएगा। तभी सभी पार्टियों के नेता इस दुविधा में पड़े हैं कि अगले 15 दिन में उम्मीदवारों की सूची घोषित हो या नहीं। व्यापर रहे चुनाव आयोग ने अभी तक चुनावों की घोषणा नहीं है। अगर पांच राज्यों के पिछले विधानसभा चुनावों के शिड्यूल के हिसाब से देखें तो अक्टूबर के पहले या ज्यादा से ज्यादा दूसरे हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो जानी चाहिए। चुनाव आयोग की टीमें राज्यों का दौरा कर रही हैं और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रही हैं। सो, पहला यक्ष प्रश्न है कि क्या चुनाव आयोग 14 अक्टूबर तक चलने वाले श्राद्ध पक्ष में चुनाव की घोषणा करेगा या पितृपक्ष समाप्त होने और नवरात्रों के शुरू होने का इंतजार करेगा। दूसरा यक्ष प्रश्न यह है कि पार्टियां क्या करेंगी? भाजपा ने मध्य प्रदेश के 79 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है और छत्तीसगढ़ में भी पहली सूची में 21 नामों की घोषणा हुई है। इन दोनों राज्यों में ज्यादातर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा रुकी है। राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के लिए तो कोई नाम तय नहीं हुआ है। कांग्रेस ने अभी किसी राज्य में उम्मीदवार तय नहीं किए हैं या नाम की घोषणा नहीं की है। उसकी चुनाव समिति की बैठक भी नहीं हुई है। दोनों पार्टियों में धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिष आदि को मानने वाले नेता चाहते हैं कि नवरात्रों में ही नाम की घोषणा की जाए। हालांकि कई नेता मानते हैं कि नाम घोषित होने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ नामांकन पितृपक्ष में नहीं होना चाहिए। नेताओं की यह दूसरी इच्छा पूरी हो सकती है। बहरहाल, देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा और कांग्रेस का आलाकमान क्या करता है और चुनाव आयोग क्या करता है?

पोल खोलने से नहीं, झूठ बोलने से बात बनेगी

विपक्षी पार्टीयां क्या कर रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ की पोल खोलने में लगी हैं। उनको लगता है कि लोगों को बताएंगे कि मोदी ने कितने झूठ बोले हैं तो लोग यकीन करेंगे और उनका साथ छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। झूठ की पोल खोलने का क्या मतलब है? उससे लोगों पर कुछ भी असर नहीं होगा, बल्कि उससे बड़ा झूठ बोलने पर फायदा होगा। सोचें, क्या देश के करोड़ों करोड़ लोगों को पता नहीं है कि उनसे झूठ बोला गया है? हो सकता है कि भारत के विश्व गुरु होने वाले झूठ के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हों लेकिन जो बातें उनकी जिंदगी से जुड़ी हैं उनके बारे में तो उनको पता ही होगा। क्या वे नहीं जानते हैं कि उनके बच्चे नौकरी के लिए भटक रहे हैं? क्या उनको पता नहीं है कि उनकी बचत घट रही है और रोजमारा की जरूरत के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है? महंगाई क्या उनको नहीं चुभ रही है? क्या किसान नहीं जान रहे हैं कि खेती उनके लिए घाटे का सौंदा बन गया है? क्या नौजवान बेरोजगारी की मार नहीं महसूस कर रहा है? पांच किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े लोगों को अपमान का अहसास नहीं हो रहा होगा? जिनके प्रियजन ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में मर गए या जमीनें बेच कर जिन लोगों ने काले बाजार से कोरोना के इलाज के इंजेक्शन खरीद थे क्या उनको हकीकत का अहसास नहीं है? मतलब जिसको फर्स्ट हैंड एक्सपरियंस कहते हैं वह तो देश के करोड़ों लोगों को हो ही रहा है। फिर भी अगर वे उस पर यकीन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी कड़ीशनिंग ऐसी है। वे सपनों में जीना पसंद करते हैं। तभी बॉलीवुड की फिल्में उनको आकर्षित करती हैं। जिस तरह से सिनेमा यकीन दिलाने की कला है। थियेटर में जाने वाले लोग थोड़े समय के लिए अपने तर्क, अपनी समझ और अपनी मान्यताओं को बाहर छोड़ कर जाते हैं, जिसे 'विलफुल सस्पेंस ऑफ बिलीफ' यानी स्वेच्छा से अपनी समझदारी का परित्याग करना कहते हैं उसी तरह राजनीति में भी होता है। राजनीति भी जनता को यकीन दिलाने की कला है। कोई नेता कैसे अपने झूठ को लोगों के दिमाग में इस तरह बैठा सकता है कि वह उसी पर यकीन करे, उसी को सच माने उससे ही नेता की काबिलियत और उसकी सफलता तय होती है। झूठ की पोल खोल कर अगर लोगों को हकीकत की दुनिया में लाने का प्रयास किया गया तो बड़ी असफलता मिलेगी। भारत की फिल्मों से यह जगजाहिर है। भारत की सचाई दिखाने वाली फिल्में व्यावसायिक रूप से कभी सफल नहीं होती हैं। उसे आलोचकों की तारीफ मिलती है, दर्शकों का प्यार नहीं मिलता है। राजनीति में भी बुद्धिमान लोग विपक्ष के एंजेंडे की तारीफ कर सकते हैं लेकिन चुनाव तो जनता के प्यार से जीता जाएगा। वह कहां है विपक्ष के पास?

स्वस्थ व मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान आवश्यक

- पहला आम चुनाव में पहली बार
45.7 प्रतिशत मतदाता वोट डाले
- हर वोट देश के नवनिर्माण में
महत्वपूर्ण

लेखक - एल.डी. मानिकपुरी,
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

पर वही अज्ञाती के बाहू महामो बढ़ी ।

दस का जनकों के बाद राष्ट्रपति चुना गया। वही कि लोक सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचन के लिए सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। घोर पिछड़ेपन, घोर दरिद्रता तथा घोर निरक्षरता वाले, नए-नए स्वाधीन हुए देश में हर नागरिक को जिसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो (अब घटाकर 18 कर दी गई है) और जो किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्तविकृति, अपराध या भ्रष्ट अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा अयोग्य न हो, वोट का अधिकार देन संविधान निर्माताओं के लिए एक बहुत बड़ी आस्था और जनसाधारण में विश्वास का काम था (अनुच्छेद 326)। अनुच्छेद 324 कहता है कि एक निर्वाचन आयोग होगा। वह संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के वास्ते तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के वास्ते सभी निर्वाचनों का अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण करेगा। देश की आजादी के बाद जुलाई 1948 को ही भारतीय नेताओं ने चुनावी प्रक्रिया की तैयारियां शुरू कर दी थी। हालांकि तब-तक चुनाव कराने के लिए कोई कानून नहीं थे। डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर के नेतृत्व में

ड्राफ्टिंग कमिटी (मसौदा समिति) ने कड़ी मेहनत कर संविधान का मसौदा तैयार किया था, जो 26 नवंबर, 1949 को पारित हुआ। हालांकि, इसे लागू 26 जनवरी, 1950 से किया गया। भारत को उस दिन चुनाव कराने के लिए नियम और उप-नियम मिले और देश आखिरकार 'भारत गणराज्य' बना। यह एक असाधारण सफर की महज़ शुरूआत थी। वैसे तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था लेकिन पहले चुनाव 1951 में हो पाए और बीच के वर्षों में भारत, किंग जॉर्ज टप के अधीन संवैधानिक राजतंत्र था। साथ ही, लुई माउंटबेटन इसके गवर्नर जनरल थे। यह जानना जरूरी है कि आज़ाद भारत के पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर, 1951 और 21 फ़रवरी, 1952 के बीच हुआ था। संविधान लागू होने के बाद चुनाव आयोग का गठन किया गया चुनाव कराने की ज़िम्मेदारी भारतीय नौकरशाह, सुकुमार सेन को दी गई। इस तरह वे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने। इसमें सबसे बड़ी चुनौती थी भारत की आबादी, जो उस समय करीब 36 करोड़ थी। दुनिया की आबादी का करीब 17 प्रैसदी हिस्सा मतदान करने वाला था। यह उस समय का सबसे बड़ा चुनाव था। चुनाव में करीब 1,874 उम्मीदवार और 53 राजनैतिक पार्टियां उत्तरी थीं, जिनमें 14 राष्ट्रीय पार्टियां थीं और इन दलों ने 489 सीटों पर चुनाव लड़े थे। संविधान के लागू होने पर, भारत ने वोट डालने के लिए उसी उम्र को योग्य माना जो दुनिया भर में अपनाई जा चकी थी। इससे 21 साल से ज्यादा उम्र वाले लगभग 17.3 करोड़ लोग वोट डालने के लिए योग्य पाए गए। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तय किए जाने थे, जो



1951 में हो पाया। अशिक्षित आबादी, चुनाव चिह्न डिज़ाइन, मतपत्र और मतदान पेटी, मतदान केंद्र आदि समस्या व चुनौती थी। साथ ही यह पक्का करना था कि मतदान केंद्रों के बीच सही दूरी हो मतदान अधिकारियों को नियुक्त कर प्रशिक्षण सहित अनेक परेशानियों और चुनौतियों का सामन भी करना पड़ा। हालांकि इन चुनौतियों को पार करने में समय लगा। अखिर में जब चुनाव हुए, तो योग्य आबादी में से 45.7 प्रतिशत मतदाता, पहली बार वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकले। इस तरह भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना, जहां लोगों ने, लोगों के लिए एक सरकार चुनी। एक वोट या एक मतदान देश व प्रदेश के लिए क्या उपयोगी साबित होगी? मतदान का महत्व कितना है? और क्यों हैं? इस विषय पर अनेक पुस्तकें लिखे जा चुके हैं, लेकिन क्या

जी20 को एक प्रमुख मंच के रूप में स्थापित

लक्ष्मी पुरी

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 20 वर्षों में एक बार मिलने वाली जी20 की इंडिया यानी भारत की अध्यक्षता ऐतिहासिक मानी जाएगी। इस अध्यक्षता ने एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है जिसकी अनदेखी करना घरेलू और विदेशी आलोचकों के लिए भी कठिन होगा। भारत की भौतिक, सांस्कृतिक, सभ्यतागत भव्यता और इसकी आर्थिक, वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति एवं गतिशीलता पूरी तरह से परिलक्षित हुई।

भारत की कूटनीतिक व सर्वसम्मति निर्माण कौशल और सबसे अधिक आवादी वाले एवं युवाओं की संख्या के मामले में सबसे समृद्ध तथा सबसे पुराने, सबसे बड़े एवं सबसे अधिक विविधतापूर्ण लोकतांत्रिक देश की हैसियत ने इस जनता के जी20' में इसकी अध्यक्षता को एक विशेष गरिमा प्रदान की। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की असाधारण प्रतिबद्धता ने भारत को विश्वगुरु' और विश्वमित्र' के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित कर दिया। भारत की यह छवि उच्चतम स्तर की भागीदारी और एक सार्थक दिल्ली घोषणा में दिखाई दी। यह परिधि से निकलकर वैश्विक आर्थिक निर्णय-प्रक्रिया के केन्द्र में पहुंचने की भारत की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। भारत ने यह संकेत दिया कि वह उत्तर-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने और संवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसकी सामाजिक न्याय की विशाल परियोजनाएं ग्लोबल साउथ के देशों में प्रतिकृति और विस्तार की दृष्टि से मानक बनती हैं। तीव्र आर्थिक विकास, सतत विकास, जलवायु कर्तव्याई और सभी के लिए मानवीय प्रतिक्रिया से लैस वैश्विक सार्वजनिक कल्याण सनिश्चित करने के विकसित एवं विकासशील देशों के मानव-केन्द्रित दृष्टिकोण जी20 की भारत की सफल अध्यक्षता की पहचान बन गया। एक अभिजात्य बहुपक्षीय मंच के तौर पर, जी20 का जन्म 2008 के वैश्विक संकट के दौरान हुआ था। इसने वास्तविक सार्वभौमिक बहुपक्षीय मंच से वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय सासन के एजेंडे को अपहृत कर लेने की आलोचना को सहते हुए इस संकट से उबरने में काफी हद तक मदद की। पिछले कुछ वर्षों में, जी20 ने अपनी उपयोगिता साबित की है। लेकिन, अब इसे अब तक के गंभीरतम संकटों से निपटना है। अतिव्यापी और आपस में एक-दूसरे से परस्पर जुड़े हुए ये संकट एक साथ उभरे हैं। इन संकटों में जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरणीय क्षरण से लेकर कोविड-19 से उपजे व्यापक सामाजिक-आर्थिक विनाश, रूस-यूक्रेन युद्ध, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, भोजन, उर्वरक, ईंधन एवं वित्तीय संकट और आपूर्ति वृद्धिला की असुरक्षा शामिल हैं, जो ग्लोबल साउथ के देशों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। यह सब एक ऐसे समय में हो रहा है जब संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन जैसे बहुपक्षीय संस्थान संयुक्त राष्ट्र महासंचिव गुटिरेज के शब्दों में भारी शिथिलता के शिकार हो गए हैं। 18वें जी20 शिखर सम्मेलन में दक्षिणी दुनिया के देशों से किए गए प्रधानमंत्री श्री मोदी के बादे झ़़ आपकी आवाज भारत की आवाज है, आपकी प्राथमिकताएं भारत की प्राथमिकताएं हैं - को प्रभावशाली और टोस तरीके से निभाया गया है। भारत ने 54 देशों वाले अफ्रीकी संघ - दूसरे सबसे बड़े संसाधन संपन्न महाद्वीप, जहाँ 1.466 बिलियन लोग सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को

पाने के लिए जूँझ रहे हैं - को जी20 में शामिल करके वैश्विक शासन की समावेशिता एवं लोकतंत्रीकरण की राह में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जी20 की अध्यक्षता के लिए भारत की सभी सात विषयागत प्राथमिकताओं का जहां तक प्रश्न है, इसने वास्तव में ग्लोबल साउथ के देशों के लिए समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्योन्मुख और निर्णायक परिणाम दिए हैं। इन परिणामों में एसडीजी को हासिल करने की दिशा में हुई प्रगति में तेजी लाना तथा जी20 कार्ययोजना एवं उच्चस्तरीय सिद्धांतों को लागू करना; वित्तपोषण के मामले में व्यापार अंतर को पाठने तथा यूएनएसजी के एसडीजी संबंधी प्रोत्साहन का समर्थन करने हेतु सभी स्त्रों से किफायती, पर्याप्त एवं सुलभ वित्तपोषण जुटाना; जी20 रोडमैप के अनुरूप स्थायी वित्त को बढ़ाना; खाद्य सुक्ष्मा एवं पोषण से संबंधित दक्षन उच्चस्तरीय सिद्धांतों के अनुरूप वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, खाद्यान्त्रों एवं उर्वरकों की कीमतों में व्यापार अस्थिरता से निपटना और आईएफएडी संसाधनों को बढ़ाना शामिल है। एक 'स्वास्थ्य' के दृष्टिकोण को अपनाते हुए, जी20 ने सहयोग का एक व्यापक पैकेज अपनाया, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व वाली महामारी से जुड़ी तैयारियों एवं निगरानी प्रणालियों को बढ़ाना और स्वास्थ्य सहयोग को वित्तपोषित करना शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पेरिस प्रतिबद्धताओं को लागू करने के मजबूत संकल्प के साथ ठोस हरित विकास समझौता थी। प्रधानमंत्री मोदी के लाइफ मिशन को सतत विकास के लिए जीवनशैली से संबंधित जी20 के उच्चस्तरीय सिद्धांतों में रूपांतरित कर दिया गया। इसने हरित जलवायु कोष (ग्रीन क्लाइमेट फंड) की महत्वाकांक्षी टूसरी पुनर्पूर्ति और निजी वित्त और जलवायु अनकल प्रौद्योगिकियों के विकास, साझाकरण, तैनाती और वित्तपोषण और बहुवर्षीय तकनीकी सहायता योजना (टीएप्पी) कार्यान्वयन पर मजबूत प्रतिबद्धता का आह्वान किया। इसने अपने एनडीसी को लागू करने के लिए 2030 से पहले ग्लोबल साउथ के देशों के लिए 5.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जरूरत और अकेले स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए चार ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जरूरत को रेखांकित किया। इसने विभिन्न पक्षों से 100 बिलियन की पेरिस प्रतिबद्धता को लागू करने और एक महत्वाकांक्षी, पता लगाने योग्य एवं पारदर्शी नए समृद्धिक मात्रात्मक लक्ष्य (एनसीव्यूजी) को निर्धारित करने का आह्वान किया। न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन के संबंध में, ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के उच्चस्तरीय सिद्धांतों द्वारा संचालित ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर सुधारांभ किया गया। जी20 ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के सुधारांभ के लिए भी संदर्भ प्रदान किया। प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के संबंध में, इसने जी20 2023 वित्तीय समावेशन कार्य योजना, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की प्रणालियों के लिए जी20 फ्रेमवर्क और एक वैश्विक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित रिपोजिटरी के निर्माण व रखरखाव की भारत की योजना का समर्थन किया। कम आय वाले देशों में डीपीआई के लिए क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और वित्त पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के बन पश्चूचर एलायंस (ओएफए) के भारत के प्रस्ताव का स्वागत किया गया। क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए एक साझा एफएसबी एवं एसएसबी कार्ययोजना तथा एक व्यापक एवं समन्वित नीतियों एवं नियामक ढांचे के लिए एक रोडमैप निर्धारित किया गया।

अज़रबैजान ने मौके का फायदा उठाया...

१५८

कल्पेआम तो टल गया लेकिन उसने बड़े पैमाने पर पलायन का स्वरूप ले लिया। पिछले हफ्ते अजरबैजान ने अपनी ही नागोर्नो-काराबाख पर सैन्य आक्रमण किया जिसमें केवल एक दिन में 200 से अधिक लोग मारे गए। लेकिन अगले दिन ही युद्धविराम कायम हो गया और क्षेत्र में सक्रिय अर्मेनियाई अलगवावार्द आत्समर्पण करने और अपने संगठन को भग करने के लिए राजी हो गए। इसका मतलब हुआ अजरबैजान की जीत। इस इलाके में तीन साल पहले तैनात की गई रुस की शांतिसेन की मध्यस्थता से हुए इस समझौते के एक अर्थ है नागोर्नो-काराबाख का अर्ध-स्वतंत्र राष्ट्र के दर्जा समाप्त हो जाना। अभी तक 13,000 लोग इस इलाके से आर्मेनिया के लिए पलायन कर चुके हैं। रास्ते में एक पेट्रोल स्टेशन पर हुए बम विस्फोट में 200 लोग घायल हो गए। आर्मेनिया की सीमा पर गाड़ियों का रेलमपेल है और देश के प्रधानमंत्री निकोल पशिण्यान ने चेतावनी दी है कि क्षेत्र में नस्लीय सफाई जारी है वहां के बहुत से लोग अपने जीवन में दूसरी या तीसरी बार शरणार्थी बन गए हैं। नागोर्नो-काराबाख में आर्मेनियाई रहते हैं लेकिन यह औपचारिक रूप से अजरबैजान का हिस्सा है और यहां पिछले तीन दशकों में खून-खारे भरे दो बड़े युद्ध हो चुके हैं। सन् 2020 में हुए अंतिम युद्ध में अजरबैजान ने कई ऐसे इलाके पर कब्जा कर लिया जो सन् 1990 के दशक से आर्मेनियाई सुरक्षा बलों के नियंत्रण में थे। अजरबैजान के हालिया हमले को भी ‘आतंकी विरोधी कार्यवाही’ कहा गया जिसका उद्देश्य संवैधानिक व्यवस्था दुबारा स्थापित करना था। और अजरबैजान ने एक दिन में वह हासिल कर लिया जो वह पिछले तीन दशकों में नहीं कर पाया था। लेकिन नागोर्नो-काराबाख पर सैन्य आक्रमण और उसके नतीजे में एक मानवीय त्रासदी उत्पन्न कर अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहम एलियेव ने पश्चिम को नाराज कर लिया है। पिछले सप्ताह जर्मनी



की विदेशर्मत्री अनालेना बेयरबोक ने बाकू को बलप्रयोग न करने के बार-बार दिए गए आश्वासन को तोड़ने, जिसके नतीजे मैं पहले से ही बदहाल लोगों को जबरदस्त कष्ट झेलना पड़ रहा है कि का दोषी ठहराया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि अज़रबैजानी सरकार 'निरंकुश' है। पश्चिम में यह व्यापक मार्यादा है कि शांति कायाम रखने की जिम्मेदारी निभा रहे रूसियों ने अज़रबैजान की मदद की क्योंकि हाल के महीनों में आर्मेनिया का द्वाकाव पश्चिम की ओर बढ़ गया है। जहां तक अज़रबैजान का सवाल है, कहा जाता है कि वह कई सालों से कथित 'कैवियार कूटनीति' का सहारा ले रहा है अर्थात् धन और उपहारों के जरिए यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। गार्जियन ने एक खबर में खुलासा किया है कि अज़रबैजान ने ब्रिटिश कंपनियों के एक गुप्त नेटवर्क के जरिए यूरोप में अपनी समर्थकों, पैरवी करने वालों और राजनीतिज्ञों को भेंट देने के लिए 2.9 अरब डालर देश से बाहर भेजे। यह पैसा लक्ज़री गुड्स और सेवाएं हासिल करने और अज़रबैजान के प्रभावशाली लोगों के लिए मनी लांडिंग करने के लिए भी प्रयुक्त हुआ। अज़रबैजान की 'कैवियार कूटनीति' का नतीजा यह हुआ कि यूरोप

ने 2020 के नार्गेंनो-काराबाख युद्ध में बाकू द्वारा किए गए अत्याचारों को नजरअंदाज कर उससे नजदीकी कायम कर ली। सन् 2022 में रूस के अलावा पेट्रोलियम प्रदाय के नए विकल्प ढूँढ़ रहे यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उरसुला वोन डेर लेयन बाकू पहुंचे और उहोंने अज़रबैजान को एक 'महत्वपूर्ण' एवं 'विश्वसनीय' ईर्धन सप्लायर बताते हुए उसकी प्रशंसन की और एक समझौते की घोषणा की जिसके अंतर्गत सन् 2027 तक ईर्यू द्वारा अज़रबैजान से खरीदी जाने वाली गैस की मात्रा दुगनी की जाएगी। अज़रबैजान हालाँकि नार्गेंनो-काराबाख के निवासियों को आश्वस्त कर रहा है कि उनका नुकसान नहीं किया जाएगा लेकिन ये लोग भयभीत हैं। अलगावादियों द्वारा युद्धविराम स्थीकारने और हथियार छोड़ने के लिए राज छोड़ने के बाद से अब तक केवल 70 टन खाद्यान्न की राहत सामग्री की एक खेप को वहां आने की अनुमति दी गई है। आर्मेनियाई जातीय समूह के नेताओं का कहना है कि हजारों लोग छत और भोजन से मरहम हैं और तलघरों, स्कूल के भवनों और खुले में सोने पर मजबूर हैं। जहां तक पश्चिम और अन्य देशों का सवाल है, वे कुछ खास नहीं कर रहे हैं। गार्जियन ने एक खबर

में खुलासा किया है कि अजरबैजान ने ब्रिटिश कंपनियों के एक गुप्त नेटवर्क के जरिए यूरोप में अपनी समर्थकों, पैरवी करने वालों और राजनीतिज्ञों को भेंट देने के लिए 2.9 अरब डालर देश से बाहर भेजे। यह पैसा लक्जरी गुड्स और सेवाएं हासिल करने और अजरबैजान के प्रभावशाली लोगों के लिए मनी लांडरिंग करने के लिए भी प्रयुक्त हुआ। अजरबैजान की 'कैवियार कूटीति' का नतीजा यह हुआ कि यूरोप ने 2020 के नार्गोनो-काराबाख युद्ध में बाकू द्वारा किए गए अत्याचारों को नजरअंदाज कर उससे नजदीकी कायम कर ली। सन् 2022 में रूस के अलावा पेट्रोलियम प्रदाय के नए विकल्प ढूँढ़ रहे यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उरसुला वोन डेर लेयन बाकू पहुंची और उन्होंने अजरबैजान को एक 'महत्वपूर्ण' एवं 'विश्वसनीय' ईंधन सप्लायर बताते हुए उसकी प्रशंसा की और एक समझौते की घोषणा की जिसके अंतर्गत सन् 2027 तक इयू द्वारा अजरबैजान से खरीदी जाने वाली गैस की मात्रा दुगानी की जाएगी। अजरबैजान द्वारा नार्गोनो-काराबाख में आतंक और बल का सहारा लेने और यूक्रेन पर रूसी हमले के जारी रहने से इयू और पश्चिम दुविधा में है। सर्दियां आ रही हैं और गैस की मांग बहुत बढ़ेगी और साथ ही 'कैवियार' की ज़रूरत भी। एक ओर हैं उनके अपने और अपनी जनता के हित और दूसरी ओर हैं इंसाफ का साथ देने का दबाव। एक न्यायपूर्ण दुनिया में छँ भले ही हम उसे काल्पनिक मानें छँ अजरबैजान पर उसके द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के चलते तत्काल प्रतिबंध लगा दिए गए होते। आशावादी आर्मेनियाईयों की यही मांग है कि अजरबैजान पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाएं जो अपनी गैस और तेल की कमाई का उपयोग अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए कर रहा है। लेकिन अब तक पश्चिम अजरबैजान पर प्रतिबंध लगाने की संभावनाओं पर 'विचार' ही कर रहा है। और पश्चिम के नेताओं के विचारों में ढूँढ़े होने के कारण साधी गई चुप्पी का प्रभाव दुनिया में हो रही घटनाओं पर साफ नजर आ रहा है।

व्यापार समाचार

टेस्ला ने चीन में अपडेटेड मॉडल वाई इलेक्ट्रिक कार की लॉन्च

हाँगकांग (एजेंसी)। एलन मस्क द्वारा संचालित टेस्ला ने चीन में अपडेटेड डिजाइन और परफॉर्मेंस में बदलाव के साथ लगभग 263,900 युआन (37,000 डॉलर) की शुरुआती कीमत पर एक नई मॉडल वाई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है। नई कार चीन में संस्थानित हाईटेंड मॉडल 3 को फॉलो करती है, जिसने पिछले महीने की शुरुआत में यूरोप में भी धूम मचाई थी। मॉडल वाई में अब 0-100 किमी/घण्टा का समय 5.9 सेकंड है। द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार, ईवी में रिफेश मॉडल 3 की तरह नए पहिये और डेंग में एलईडी लाइटिंग स्ट्रिप है। टेस्ला 299,900 युआन (लगभग 42,000 डॉलर) में एक लॉन्च-अंज वर्जन और 349,900 युआन (लगभग 49,000 डॉलर) में हाईटेंड मॉडल वर्जन भी पेश कर रहा है। कंपनी ने अभी तक अमेरिका में अपडेटेड मॉडल वाई की घोषणा नहीं की है। अगस्त में, टेस्ला ने अपने प्रमुख मॉडल एस एक्स को अमेरिका और कनाडा में अधिक किफायती कीमतों पर मानक वेरिएंट के साथ लॉन्च किया, और प्रीमियम ईवी कार मॉडल में कंपोनेंट्स के बीच इसमें 10,000 डॉलर की कटौती की। टेस्ला की आधिकारिक वेबसाइट पर, मॉडल एस स्टैंडर्ड रेंज की कीमत अब विकल्पों से पहले 88,490 डॉलर है। मॉडल एस स्टैंडर्ड रेंज की कीमत अब 0-100 की रेंज और 3.7-सेकंड, 0-60 मील प्रति घण्टे का समय प्रदर्शन करता है। वास्तव में 149 मील प्रति घण्टे की टांप स्टैंड भी है। टेस्ला मॉडल एक्स रेंडर्ड रेंज अब विकल्पों से पहले 88,490 डॉलर की शुरुआती कीमत पर पेश की गई है। यूरोप पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एस्यूवी प्राप्त कर सकते हैं जिसमें प्रति चार्ज 269 मील की रेंज और 4.4 सेकंड में 0-60 मील प्रति घण्टे की गति होती है।

सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में हुई बड़ी कटौती

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई में रहने वालों के लिए एक रहात भरी खबर है। महानगर गैस टिमिंटेड ने एक बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने मुंबई और उसके आसपास के उपनगरों में सीएनजी की कीमतों में 3 रुपए प्रति किलोग्राम की कटौती की है। इसके साथ-साथ घेरेलू पीएनजी की कीमत में भी 2 रुपए कीमी की घोषणा की है। इसके साथ ही मुंबई और उसके आसपास के उपनगरों में सीएनजी की नई कीमत 47 रुपए हो गई है। वहाँ, घेरेलू पीएनजी की कीमत 47 रुपए हो गई है। महानगर गैस लिमिटेड की ओर से कीमतों में कमी का आदेश 1 अक्टूबर 2023 की मध्यरात्रि और 2 अक्टूबर 2023 की सुबह से लागू हो जाएगा। इससे पहले अप्रैल महीने में भी महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में 8 रुपए और पीएनजी की कीमत में 5 रुपए प्रति एस्यूएम्प की कटौती की थी। कीमतों में कटौती के बाद मुंबई और उसके उपनगर में सीएनजी की कीमत 79 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई थी। वहाँ, पीएनजी की कीमत 49 रुपए हो गई थी। कटौती से पहले शहर में सीएनजी की कीमत 87 रुपए प्रति किलोग्राम थी जबकि पीएनजी की कीमत 54 रुपए प्रति एस्यूएम्प थी।

हर मिनट 142,690 डॉलर कमाने के दावे पर मस्क ने दिया जवाब, कहा- भारी नुकसान उठाता हूं

नई दिल्ली (एजेंसी)। टेक अरबपति एलन मस्क ने रविवार को उन खबरों का खंडन किया कि वह हर मिनट 142,690 डॉलर या प्रति घण्टे 8,560,800 डॉलर कमाते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी टेस्ला के स्टॉक में गिरावट आती है तो वह अधिक पेशा गत्वा देते हैं। एक यूजर को जावाब देते हुए, एक्स के मालिक ने कहा कि ऐसे रिपोर्ट मूर्खात्मक मैट्रिक्स पर निर्भर करती हैं। मस्क ने पोस्ट किया, यह नकदी का ढेर नहीं है। वास्तव में मेरे पास उन कंपनियों में स्टॉक हैं जिन्हें बनाने में मैंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से, बहर बार टेस्ला के स्टॉक में बेरतीव गिरावट से उहें कहीं अधिक नुकसान होता है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि तीन साल की अवधि के दौरान को कुल संपत्ति औसतन लगभग 2,378 डॉलर प्रति सेकंड बढ़ी। रिपोर्ट में दावा किया, यह प्रति मिनट 142,680 डॉलर या प्रति घण्टा 8,560,800 डॉलर है। आप वह आठ घंटे के लिए विस्तर पर जाते हैं, तो आपनी सुवह वह उत्तर है और खुद को 68,466,400 डॉलर अधिक अमीर पाते हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ ने जनवरी से जून 2023 तक अपनी कुल संपत्ति में 96.6 बिलियन डॉलर की वृद्धि दें जाती है। वह वर्तमान में 248.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। टेस्ला में मस्क की फिलहाल 23 फीसदी हस्सेदारी है। उनकी संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, लगभग दो-तीन बिलियन डॉलर की सफलता से जुड़ा है। मस्क ने अक्टूबर, 2022 में तब सुधार्यों बटोरीं, जब उन्होंने ट्रिवटर को 44 बिलियन डॉलर में खरोदा और फिर उसका नाम एस्स रख दिया। ब्यूमर्बन की रिपोर्ट के मुताबिक, टेस्ला के शेरों में हालिया गिरावट के बाद मस्क की संपत्ति गिरकर 137 अब डॉलर हो गई है।

पॉपुलर हीकल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड ने सेबी के पास दाखिल किया डीआरएचपी

रायपुर। भारत की अग्रणी विविधकृत ऑटोमोबाइल डीलर, पॉपुलर हीकल्स एंड सर्विसेज टिमिंटेड (कंपनी) ने बाजार नियमक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के पास ड्राफ्ट रेड हेंगिंग प्रारंभिक्स्टम (डीआरएचपी) दाखिल किया। कंपनी वित्त वर्ष 2023 में दर्ज आय के लिहाज से, भारत की अग्रणी विविधकृत ऑटोमोबाइल डीलरशिप है, (सोसीटी: क्रिसिल रिपोर्ट) जिसके पास पूरी तरह से एकीकृत व्यवसाय मॉडल है। कंपनी इस इशु के जरूरी तहत इक्कीटी शेरों (अंकित मूल्य 2) के फ्रेश इशु के जरूरी 250 करोड़ तक जुटाना चाहती है और 14,275,401 इक्कीटी शेरों का आफर फार मेल (ओएम्स) पेश करना चाहती है। (कुल आफर का आकार) कंपनी ने फ्रेश इशु के जरिये जुटाई गई राशि का उपयोग, कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा लिए गए 192 करोड़ के ऋण के पूर्ण या आधुनिक पुर्णपूर्णतान और या पूर्व-भूतान करने और और शेष राशि का इस्तेमाल सामान्य कांपोरेट उद्देश्यों के लिए करने का प्रस्ताव किया।

भारत तीरंदाजी में सभी छह टीम स्पर्धाओं के क्वार्टर फाइनल में

हाँगझोउ (एजेंसी)। भारतीय तीरंदाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सोमवार को एशियाई खेलों में सभी टीम स्पर्धाओं में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत ने पांच टीम एलिमिनेशन दौर खेले और सिर्फ एक सेट गंवाया। वहाँ महिला कंपाउंड टीम को क्लाइंफिकेशन में शीर्ष रहने के कारण क्वार्टर फाइनल तक बाय मिला था।



में तीन 10 स्कोर करके 2 . 0 की बढ़त बना ली थी। लेकिन भारत अंक के अंतर से गंवा दिया। वहाँ तीसरे सेट में दास और अंकित ने शानदार प्रदर्शन करते

मलेशियाई टीम ने दूसरा सेट एक बढ़त बना ली थी। लेकिन भारत अंक के अंतर से गंवा दिया। वहाँ तीसरे सेट में दास और अंकित ने शानदार प्रदर्शन करते

हुए तीन परफेक्ट 10 लगाये और क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली जहाँ उनका सामना चौथी वरीयता प्राप्त इडोनेशिया से होगा।

इडोनेशिया को हराने पर उनकी टक्के शीर्ष रैंकिंग वाली दक्षिण कोरिया से हो सकती है। एशियाई खेलों में छह कोटा स्थान उत्तरव्य है जो स्टिक्वर मिश्रित टीम विजेता और व्यक्तिगत वर्ग में शीर्ष दो तीरंदाजों को मिलेंगे। कंपाउंड मिश्रित वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त ओजस देवताले और ज्योति सुरेश वेंक्रम ने सिर्फ एक अंक और अंकित वरीयता प्राप्त अलावा देश के 225 . 218 से हराया। दास, धीरज और तुषार शेल्क की पुरुष स्टिक्वर टीम ने 159 . 151 से मात्र दी। अब उनका सामना मलेशिया से होगा। कंपाउंड टीम वर्ग में दूसरी वरीयता प्राप्त इडोनेशिया से होगी।

केनोइंग और क्याकिंग में भारत धोनी से बहुत कुछ सीखा लेकिन कसानी का मेरा अपना तरीका : गायकवाड़ के लिये निराशाजनक दिन



हाँगझोउ (एजेंसी)। भारतीय फाइनल में उत्तरने के बावजूद वे खिलाड़ियों के लिये केनोइंग पदक नहीं जीत सके। नीरज और क्याकिंग का मलेशिया का एकल एकल को निराशन करने के लिए आठवें स्थान पर रही।

सेकंड का समय निकालकर सातवें स्थान पर रहे। रीवासन सिंह एन और फिलेम जानेश्वर सिंह एन और फिलेम जानेश्वर सिंह की भारतीय टीम पुरुष मलेशिया को ब्राउन 500 मीटर फाइनल में चारों युगल 500 मीटर के समय आठवें स्थान पर रही। महिला टीम के बाद अब भारतीय पुरुष किंकट टीम भी स्वर्ण पदक की दावेदार होगी। भारतीय टीम मंगलवार को क्राउटर फाइनल में आखिरी स्थान पर रही। बिनिता चानू औरोनम और वार्षी गोती ने युगल 500 मीटर में दावाक युगल 500 मीटर में 4 = 36 . 314 तिक्काल सकती।



हाँगझोउ (एजेंसी)। उन्होंने महेन्द्र सिंह धोनी से काफी कुछ सीखा है। लेकिन पहली बार एशियाई खेलों की किंकट स्पर्धा में भारतीय पुरुष टीम की काफी कमाल कर रहे रुतुराज गायकवाड़ ने कहा कि उनकी कासानी की अपनी शैली है। महिला टीम के बाद अब भारतीय पुरुष किंकट टीम भी स्वर्ण पदक की दावेदार होगी। भारतीय टीम मंगलवार को क्राउटर फाइनल में आखिरी स्थान पर रही। इंडियन प्रीमियर लीग में चारों युग

